दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 10 अप्रैल 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 190

महत्वपूर्ण एवं खास

ऑस्ट्रेलिया में धीरे-धीरे कम हो रहा कोरोना का कहर

सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में पिछले तीन सप्ताह में कोरोना वायरस के सबसे कम मामले सामने आए हैं।स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने बृहस्पतिवार को बताया कि 96 नए मामले सामने आए हैं 17 मार्च के बाद पहली बार 100 से कम मामले सामने आए हैं। 28 मार्च को सबसे अधिक 457 नए मामले सामने आए थे। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस के अब तक 6,000 मामले सामने आए और 51 लोगों की जान जा चुकी है।अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को सीमित करने के उद्देश्य से सांसदों ने बुधवार देर रात 130 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (81 बिलियन डॉलर) की एक मजदूरी सब्सिडी योजना पारित की था।

संक्रमितों का वैश्विक आंकड़ा 15 लाख पार

न्यूयॉर्क । कोरोनावायरस महामारी से संक्रमितों की वैश्विक संख्या 15 लाख से भी अधिक हो गई है। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने इस बात की जानकारी दी। समाचार एजेंसी ने सीएसएसई के नवीनतम आंकड़ों के हवाले से कहा, पूरी दुनिया में शाम 5.15 (2115जीएमटी/ स्थानीय समयानुसार) तक कोविड-19 संक्रमण से संक्रमितों का वैश्विक आंकड़ा कुल 87,706 मौतों के साथ 15,00,830 था। इस सूची में कुल 4,23,135 मामलों के साथ अमेरिका पहले, 1,46,690 व 1,39,422 मामलों के साथ स्पेन और इटली क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग के जुटाए गए डेटा के अनुसार, महामारी से संक्रमित एक लाख से अधिक मामलों वाले देशों में फ्रांस और जर्मनी भी शामिल हैं।

103 साल की महिला ने कोरोना को हराया

रोम। अदा जानुसो ने 103 साल की उम्र में कोरोना वायरस को हरा दिया। वह साहस और विश्वास के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने की सलाह देती हैं।यूरोप में इटली और फ्रांस में उम्रदराज लोगों की आबादी सबसे ज्यादा है और कम से कम 100 साल उम्र वाले ऐसे लोगों को यहां 'सुपर ओल्ड' की श्रेणी में रखा जाता हे। इटली में दुनियाभर में कोविड-19 से मौत के सर्वाधिक मामले सामने आये हैं, ऐसे में अधिक उम्र में कोरोना वायरस को मात देने वालों को प्रेरणास्रोत माना जा रहा है। जानुसो भी उनमें से एक हैं। उन्होंने लेसोना शहर में वृद्धजनों के ग्रेजिया रेजीडेंस से वीडियो कॉल में एपी से कहा, ''मैं ठीक हूं। मैं टीवी देखती हूं, अखबार पढ़ती हूं।'' अपनी बीमारी के बारे में पूछे जाने पर जानुसो ने कहा, ''मुझे कुछ बुखार था।'' उनके डॉक्टर ने बताया कि वह एक हफ्ते तक बिस्तर पर रहीं। डॉक्टर फर्नो मार्चेसी ने कहा, ''हमने उन्हें तरल पदार्थ दिये क्योंकि वह खाना नहीं खा रही थीं।'' उन्होंने बताया कि एक दिन उन्होंने आंखें खोलीं और फिर धीरे धीरे उनकी दिनचर्या सामान्य होती गई। वह पहले की तरह काम करने लगीं। जब जानुसो से पूछा गया कि उन्हें इस समस्या से उबरने में कैसे मदद मिली तो उनका जवाब था, ''साहस और शक्ति से एवं विश्वास से।

24 घंटे में कोरोना के 549 नए केस 473 लोग हुए ठीक

» अब तक 169 की मौत, संक्रमितों की संख्या 5865 हुई

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 591 मामले सामने आए है। और अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5865 हो चुकी है,जबकि अब तक 169 लोगों की मौत हुई और 473 लोग ठीक हुए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने गुरुवार का संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी देते हुए बताया कि देश में अब तक 5865 लोग इस खतरनाक वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। संयुक्त सचिव ने अग्रवाल बताया कि इस खतरनाक वायरस से अभी तक 169 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 20 लोगों की मौत कल से अभी तक हुई है। वही इस वायरस से 478 लोग ठीक हुए है और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। गौरतलब हो कि बुधवार को कोरोना वायरस के 773 नए मामले सामने आए थे और 32 लोगों की मौत हुई थी। इस प्रकार आज देश में संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। साथ ही मरने वाले लोगों की संख्या भी घटी है। संयुक्त सचिव ने अग्रवाल बताया कि इस खतरनाक वायरस से अभी तक 169 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 20 लोगों की मौत कल से अभी तक हुई है। वही इस वायरस से 478 लोग ठीक हुए है और उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अग्रवाल ने बताया कि अस्पतालों को संक्रमण नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि चिकित्सा कर्मचारी कोविड-19 के संपर्क में न आएं। उन्होंने बताया कि सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि न केवल पीपीई को चिकित्सा कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, बल्कि तर्कसंगत रूप से भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

जरुरत के हिसाब से पीपीई का इस्तेमाल- कोरोना के खिलाफ सुरक्षा क लिए पीपीई, मास्क और वेंटिलेटर्स की सप्लाई शुरू हो गई है। 1.7 करोड़ पीपीई का ऑर्डर दिया जा चुका है जिसकी सप्लाई आने लगी है। मंत्रालय ने जानकारी दी कि 49 हजार वेंटिलेटर्स ऑर्डर किए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स (पीपीई) की कमी को लेकर साफ किया है कि जहां जरूरत है, वहां पीपीई किट्स दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह पीपीई की जरूरत नहीं है। जहां खतरा है, वहां फुल कन्टेनमेंट वाली पीपीई की जरूरत पड़ती है। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जॉइंट सेक्रेट्री लव अग्रवाल ने कहा कि एन95 मास्क को 8 घंटे तक यूज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन दवा सबको ना दी जाए, जो गाइडलाइंस हैं, वही फॉलो की जाएं।

रेलवे ने तैनात किये 2,500 से अधिक डॉक्टर- अग्रवाल ने बताया कि रेलवे ने 2,500 से अधिक डॉक्टरों और 35,000 पैरामेडिक्स कर्मचारियों को मरीजों के इलाज के लिए तैनात किया है।

मरकज से महाराष्ट्र लौटे तबलीगी जमात के 28 लोग पॉजिटिव, 50 का फोन बंद

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा कर रखी हुई है। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 5700 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटो में 540 नए मामले सामने आए हैं। भारत में इस आंकड़े के बढ़ने में तबलीगी जमात के लोगों की अहम भूमिका है। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन के मरकज से निकले तबलीगी जमता के लोगों के कारण ये आंकड़े काफी ज्यादा बढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से महाराष्ट्र लौटे लोगों में से 28 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 6 विदेशी नागरिक बताए जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस स्पेशल ब्रांच ने मुंबई के धारावी इलाके से तबलीगी जमात के पांच लोगों की पहचान कर उन्हें चारंटाइन कर दिया है। वहीं दिल्ली से महाराष्ट्र लौटे कुल तबलीगी जमात के लोगों में से 50 लोगों का फोन अभी भी बंद है और वह छिपकर बैठे हुए हैं।

वहीं दूसरी तरफ मुंबई के भाटिया अस्पताल को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि बुखार का इलाज करा रहे तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिसके बाद पूरे अस्पताल को सील कर दिया गया है और इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों और मेडिकल स्टाफ की भी जांच की जा रही है।

बता दें, कोरोना के लगातार बढ़ते मामले देश के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। यही वजह है कि ज्यादातर राज्य लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 540 नए मामले सामने आए हैं जबकि 17 लोगों की मौत की खबर है। इसी के साथ देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 5734 पहुंच गई है। इसमें 5095 लोगों का इलाज चल रहा है जबकि 473 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं।

किसानों को जल्द मिलेगी राहत

» तोमर ने कृषि मंत्रियों के साथ की बैठक

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार शाम नई दिल्ली में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के साथ बैठक की। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में कृषि राज्य मंत्री पुरषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी, सचिव (एसी एंड एफडब्ल्यू) संजय अग्रवाल, विशेष सचिवों, अपर सचिव (कृषि) और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक के दौरान, राज्यों कृषि मंत्रियों, अपर प्रधान सचिवों, राज्यों के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ खेती के संचालन और कटाई, कृषि विपणन और मंडी संचालन, एमएसपी में खरीद, आगत (बीजों और उर्वरकों) के प्रावधान और रसद एवं कृषि/बागवानी उत्पादों की आवाजाही से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

उन्होंने कोविड-19 महामारी जैसे चुनौतीपूर्ण समय में भी कृषि गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए राज्यों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने लॉकडाउन अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही, कटाई और बुवाई मौसम के मद्देनजर कृषि कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छूटों पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को आश्वासन दिया कि इस अवधि के दौरान राज्यों को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिससे उन्हें उभरती हुई चुनौतियों का सामना करने में सुविधा प्राप्त होगी। राज्य के कृषि मंत्रियों ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और कहा कि कृषि कार्यों और गतिविधियों के लिए प्रदान की गई छूट से राज्यों में किसानों और कृषि गतिविधियों को काफी लाभ मिला है।

देश में 7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में भेजे गये 14 हजार करोड़

» पीएम-किसान सम्मान निधि स्कीम

नई दिल्ली (आरएनएस)। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के संकट से लड़ने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के बीच किसानों को बड़ी राहत दी है। खेती-किसानी का काम प्रभावित न हो इसके लिए देश के 7 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपये भेज दिया है। बाकी किसानों को राहत देने की प्रकिया जारी है।

सूत्रों के अनुसार यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत रजिस्टर्ड किसानों को भेजी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने डायरेक्ट बेनिफट ट्रांसफर

(डीबीटी) के माध्यम से किसानों को 14,000 करोड़ रुपये भेजे जाने की पुष्टि की है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक कुल 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में करीब 18 हजार करोड़ रुपये की रकम भेजी जानी है। शेष लोगों को पैसा भेजने की प्रकिया जारी है. खास बात यह है कि पैसा उन्हीं किसानों को मिल पा रहा है जिनका स्कीम के तहत आधार वेरीफिकेशन हो चुका है। गौरतलब है कि गरीबों और किसानों को ज्यादा असर न पड़े इसके लिए सरकार ने मार्च में ही बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था, जिसमें पीएम-किसान स्कीम को भी शामिल किया गया था, ताकि किसानों को वक्त पर पैसा मिल सके. देश में करीब 14.5 करोड़ किसान हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत सभी का वेरीफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। पीएम किसान स्कीम में सालाना 6000 रुपये मिलते हैं।

इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ

सूत्रों के अनुसार ऐसे किसान जो भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक हैं, वर्तमान या पूर्व मंत्री हैं, मेयर या जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद हैं तो वे इस स्कीम से बाहर माने जाएंगे. भले ही वो किसानी भी करते हों। केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे। केंद्र और राज्य सरकार के मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों लाभ मिलेगा।

केंद्र सरकार ने दी राज्यों के कोविड-19 इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने राज्य हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करने के मकसद से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूरा फंड देने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में खर्च के लिए दी जाने वाली पूरी रकम केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी।

केंद्र सरकार राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधन बेहतर करने के मद्देनज़र खास पैकेज

दिया है। ये पैकेज इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम को लेकर है, इसमें जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक इस प्रोजेक्ट को तीन चरणों में बांटा गया है। इसके दौरान केंद्र राज्यों को पैसा देगी। इन तीन चरणों में पहला चरण जनवरी 2020 से जून 2020, दूसरा चरण जुलाई 2020 से मार्च 2021 तथा तीसरा चरण अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक होगा। पहले फेज को लेकर पैसा भेज दिया गया इन पैसों को उपयोग कोविड हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, लैब, पीपीई, मास्क, हेल्थ वर्कर की नियुक्ति जैसी चीजों में खर्च किया जा सकेगा।

पैकेज की प्रमुख बातें

नेशनल हेल्थ मिशन की डायरेक्टर वंदना गुरुनानी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि 100 फीसदी सेंट्रल प्रोजेक्ट को जनवरी 2020 से मार्च 2024 तक चीन चरणों में लागू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में रोकथाम और राष्ट्रीय और राज्य सत्र पर हेल्थ सिस्टम को मजबूत किया जाएगा. साथ ही इसमें मेडिकल उपकरण, दवाइयों की खरीद, लैब बनाना, और बायो-सिक्योरिटी तैयारियों समेत निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना शामिल है। ये सर्कुलर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों हेल्थ कमिश्नर्स को भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि तत्काल फंड जारी किया जा रहा है। पहले चरण के तहत लागू की जाने वाली मुख्य गतिविधियों में कोविड-19 अस्पताल बढ़ाना, और अन्य अस्पतालों का विकास करना है। वहीं आइसोलेशन रूम्स, वेंटिलेटर के साथ आईसीयू, अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति, अस्पतालों में लैब को दुरुस्त किया जाएगा। इसके साथ ही पहले चरण में लैब और एंबुलेंस भी बढ़ाई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय पैकेज से राज्य में सुरक्षा उपकरण (पीपीई), एन95 मास्क और वेंटिलेटर खरीदने में सहायता की जाएगी, जो कि भारत सरकार द्वारा खरीद कर आपूर्ति की जा रही है।

ओडिशा में 6 दिन पहले ही 30 अप्रेल तक बढ़ा लॉकडाउन

» सीएम पटनायक ने की घोषणा

भुवनेश्वर (आरएनएस)। पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन की मियाद पूरी होने से 6 दिन पहले ओडिशा ने लॉकडाउन को 30 अप्रेल तक बढ़ा दिया है। ऐसा निर्णय लेने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ओडिशा के सीएम ने केंद्र से 30 अप्रैल तक ट्रेन और हवाई सेवा शुरू नहीं करने का अनुरोध किया है। राज्य में शैक्षणिक संस्थान 17 जून तक बंद रहेंगे। आपको बताते जाए कि कोरोना संकट को देखते हुए पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है।

कैबिनेट बैठक के बाद सीएम नवीन पटनायक ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर हमें लोगों की जान बचाने और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के बीच निर्णय लेना है। आज कैबिनेट ने फैसला किया कि हमारे लोगों की जान बचाना इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस कारण से हमने 30 अप्रैल तक लॉक डाउन का विस्तार करने का निर्णय किया है।

कोरोना ने बदल दिया भारत के आर्थिक विकास का नजरिया

» मंदी की गिरफ्त में आ सकती है दुनियाः आरबीआई

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोन वायरस के प्रकोप ने आर्थिक सुधार के लिए भारत के दृष्टिकोण को तेजी से बदल दिया है। कोविड -19 के फैलने से पहले 2020-21 को भारत विकास के नजरिए से देख रहा था, अब कोविड -19 महामारी ने इस दृष्टिकोण को काफी बदल दिया है, जिसके कारण पूरी दुनिया पर 2020 में मंदी छाने की आशंका है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में यह बात कही गई है, जिसके अनुसार दक्षिण एशिया के विकास के इंजन का इस महामारी ने प्रभावित किया है। 2019 के अंतिम तीन महीनों में भारत की अर्थव्यवस्था छह साल से अधिक समय में अपनी सबसे धीमी गति से बढ़ी और यह 5 फीसद ही रह सकती है, जो एक दशक में सबसे कम होगी। आरबीआई ने जैसा कि पिछले महीने अपने नीतिगत बयान में कहा था कि स्थिति अत्यधिक अनिश्चित बनी हुई है । इस वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट पर कोई अनुमान अभी लगाने से परहेज करना चाहिए। वर्तमान परिवेश को अत्यधिक तरल के रूप में वर्णित करते हुए केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह कोविड -19 की तीव्रता, प्रसार और अवधि का आकलन कर रहा है। आरबीआई ने पिछले महीने के अंत में एक आपातकालीन कदम में 75 आधार अंकों की बड़ी उधार दर में कटौती की और घरेलू बाजारों में रुपये और डॉलर की तरलता को बढ़ाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। बता दें कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 15 लाख के पार हो गई है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब दुनिया के करीब 205 देशों में फैल चुके इस कोरोना के संक्रमण की वजह से अब तक 88500 लोगों की मौत हो गई है और 15 लाख से अधिक (कुल 1518783) लोग संक्रमित हो चुके हैं।

दूसरे देशों से भारत आने वालों की जांच नहीं कराई गईः भूपेश

» कोरोना मामले पर कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना

नई दिल्ली (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि अगर विदेश से आने वालों की समय पर जांच कर उन्हें पृथक कर दिया गया होता, तो यह वायरस देश में इतना ज्यादा नहीं फैलता।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 अप्रैल को बुलाई गई मुख्यमंत्रियों की बैठक में विचार-विमर्श करने के बाद उनकी सरकार भी राज्य में लॉकडाउन (बंद) को लेकर निर्णय लेगी। बघेल ने वीडियो लिंक के माध्यम से संवाददाताओं से कहा कि हमने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर छत्तीसगढ़ में पहले से ही कदम उठाने शुरू कर दिये थे। बाहर से आने वालों की जांच की गयी। प्रशासन के स्तर पर जरूरी कदम उठाए गए। लोगों ने भी पूरा सहयोग किया। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों और मजदूरों की मदद की व्यवस्था की गई। इसमें व्यापारी और समाज के दूसरे वर्ग ने भी सहयोग किया। लॉकडाउन आगे बढ़ने की संभावना के बारे में पूछे जाने पर बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री 11

अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। इसमें हम अपने सुझाव देंगे। इसके बाद हम 12 अप्रैल को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और अधिकारियों से चर्चा करने के बाद निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से लॉकडाउन के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। बघेल ने कहा की छत्तीसगढ़ में 11 मरीज मिले हैं जिनमें से नौ स्वस्थ हो चुके हैं और वे अपने घर जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डों की जिम्मेदारी केंद्र के पास है। अगर विदेश से आने वालों की हवाई अड्डों पर ही जांच हो जाती और उन्हें पृथक कर दिया जाता तो फिर कोरोना इतना ज्यादा नहीं फैलता। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में विदेश से आने वाले 2100 लोगों की जांच की और उन्हें पृथक वास में रखा। इससे हमें कोरोना को रोकने में मदद मिली। बघेल ने यह भी कहा कि जनधन खातों में 750 रुपये महीने की दर से तीन महीने की राशि एकसाथ भेजी जाए और मजदूरों के खातों में भी तीन हजार रुपये दिए जाने चाहिए। बघेल के मुताबिक यह अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल है कि कोरोना संकट से राज्य को कितना वित्तीय नुकसान हुआ है। बघेल ने उनकी सरकार कमजोर वर्गों और गरीबों को राहत देने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगभग 65 लाख राशन कार्ड हैं जिसमें 56 लाख गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले लोग हैं। उन्हें हमने 2 महीने का राशन मुफ्त देने का फैसला किया है।